विचार बिन्दु

पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश होता है, जप से पाप दूर होता है, मौन से कलह की उत्पत्ति नहीं होती और सजगता से भय नहीं होता। –चाणक्य

शिक्षा और चिकित्सा विभाग में लागू "रोटेशन" मंत्रिमंडल पर भी लागू हो

राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों की विस्तृत जानकारी नहीं अतः राजस्थान की ही बात करना उचित होगा। राजस्थान में शिक्षा और चिकित्सा का स्तर देश में बहुत नीचा है। हाँ, यहाँ नवाचारों के नाम पर कई असफल प्रयोग किये जाते रहे हैं और उसके कारण शिक्षक और डॉक्टर को लिपिक बना दिया गया। डॉक्टर और शिक्षक खास तौर से संस्था प्रधान कम्प्यूटर पर डेटा एकत्रित करने व रिपोर्ट्स बनाने में ही वयस्त रहते हैं। शिक्षा विभाग में अनेक अन्य प्रयोगों के साथ 'शाला दपर्ण' और शाला दर्शन इसके ताज़ा उदाहरण हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्षों का रोटेशन उच्च शिक्षा की स्तरीय उन्नति हेतु ब्रह्मास्त्र की तरह लागू किया गया। प्रा.शि. एवं मा. शिक्षा में संभवतः अब इन दोनों प्रयोगों को मिलाकर 'शाला दर्पन' का पोर्टल बनाया गया है। हाल ही तथाकथित 'महान' प्रयोग चिकित्सा विभाग में भी प्रारंभ किया गया है।

लेखक को याद नहीं आता कि कभी प्राचीनकाल, मध्य युग या स्वतंत्रता पूर्व के आधुनिक काल में इन ब्रह्मास्त्रों का उल्लेख हो। पौराणिक काल में ऋषियों के आश्रम में पढ़ाई होती थी और इन ऋषियों को 'रोटेशन' से बदलने का प्रावधान नहीं था। विभिन्न राजाओं में चन्द्रगुप्त के गुरू चाणक्य से लेकर राजशाही तक राजगुरू या राजपुरोहित नहीं बदले जाते थे। चरक व सुश्रुत जैसे महान चिकित्सकों के समय से स्वतंत्रता के पूर्व तक चिकित्सा संस्थाओं में कहीं 'रोटेशन' प्रणाली नहीं सुनी जाती।

'रोटेशन' कोई विकास या सुधार का प्रयास नहीं है। यह एक राजनीतिक हथियार बन गया है, अपनी-अपनी गोटियाँ बिठाने का, सस्ती लोकप्रियता का, वोट बैंक का, भ्रष्टाचार का-कमाई का।

रोटेशन के कई स्वरूप हैं। एक है स्थानांतर। सभी विभागों में स्थानांतर होते हैं। प्रशासनिक पदों पर अमूमन तीन साल की अवधि रहती है। परंतु राजनीतिक नफा नुकसान अथवा दलीय पक्षपात के आधार पर स्थानांतर होते हैं। देखा यह जाता है कि सत्ता पक्ष के प्रति प्रतिबद्धता है कि नहीं। वोट बैंक की दृष्टि से उस क्षेत्र का जातीय समीकरण भी देखा जाता है। कुछ पदों पर यह देखा जाता है कि कौन अधिक कमाई करके सत्ता पक्ष को देगा। बड़े-बड़े केन्द्रीय व राज्य सत्ता के प्रोजेक्ट पर अधिकाधिक बचत करके सत्ता पक्ष को लाभ पहुँचाना भी उद्देश्य रहता ही है। यह हथियार हर स्तर पर प्रयुक्त हो सकता है। चपरासी, कांस्टेबल, पटवारी, शिक्षक व अन्य कर्मचारियों से लेकर मुख्य सचिव तक उपर्युक्त उल्लेखित उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानांतर होते हैं। प्रत्येक सत्ता परिवर्तन के बाद सत्ता के सभी क्षेत्रों में 'मास स्केल' पर स्थानांतर होते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी इच्छा तक वह वहीं काम करे। यदि काम खराब है तो स्थानांतर ही क्यों, नौकरी से ही निकाल दिया जाय। वी.आर.एस. में अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति में हटा दिया जाय। विशेष प्रशासनिक कारण, इच्छित स्थान, पदोन्नति, पारम्परिक स्थानांतर आदि भी उचित हैं। लेखक के पिता व माता दोनों ही प्रा.वि. के प्रधानाध्यापक रहे। स्वतंत्रता पूर्व मेवाड़ रियासत का एक छोटा सा गाँव था, एक क्वार्टर भी था। एक ही स्थान पर तीन दशाब्दी तक रहे और देवी-देवता की तरह पूजनीय रहे। मुस्लिम छात्रों को पढ़ने-लिखने अन्यत्र भेजा, उन्हें नौकरी में लगवाया। जैन संतों को पढ़ाया। सिख छात्रों को उर्दू पढ़ाई। सफाई कर्मियों तक सारे गाँव को यज्ञोपवीत समारोह में आमंत्रित किया। उनका निधन उदयपुर में हुआ, उनकी अस्थियाँ उस गाँव में ले जाई गई, तीन दिन वहाँ शोक रहा, बाल बनवाये गये। जुलूस के साथ अस्थि विसर्जन हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व से छोटी रियासत प्रधानमंत्री टी.राघवाचारी के नेतृत्व में अधिक प्रगतिशील थी आज की लोकतंत्र सरकार की अपेक्षा। प्रजातंत्र के नाम पर जनता अब प्रजा है और राजनेता शासक हैं राजा हैं। यह लोकतंत्र व जनतंत्र नहीं, 'राजा' व 'प्रजा' तंत्र है।

राजस्थान ने ऐसे कई आत्मघाती निर्णय लिये हैं। हर रोटेशन व परिवर्तन के पीछे अपने लोगों को अथवा किसी न किसी रूप में स्वार्थपूर्ति ही उद्देश्य रहता है। यह रोटेशन व 'टर्म' की कुप्रथा जितनी जल्दी समाप्त हो राजस्थान का भला होगा। यह निश्चित है कि स्तर निरंतर गिरता ही रहेगा।

स्थानांतर के बाद दूसरा हथियार विश्वविद्यालयों में और मेडिकल कॉलेज व हास्पिटल में 'टर्म' व 'रोटेशन' का है। सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालयो में विभागाध्यक्षों व प्राध्यापकों के नाम से ही विभाग यशस्वी होता था और लोग गर्व से कहते थे कि मैं अमुक प्रोफेसर का छात्र रहा हूँ। आज एक तो सी.ए.एस. (केरियर एडवान्समेन्ट) स्कीम के नाम पर हर व्यक्ति प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर हो जाता है, केवल कुलपति का चहेता होना चाहिये। साक्षात्कार मात्र औपचारिकता है। चयन व नियुक्तियों में जो धाँधली है उसके कारण अयोग्य, अक्षम, अकर्मण्य व्यक्ति भी उच्चतम पद पर पहुँच जाता है और कुलपति भी बनता है। विश्वविद्यालयों में स्तर गिरने का यह एक बहुत बड़ा कारण है। यही नहीं विभागाध्यक्ष भी ऐसी ही लोगों को बनाते हैं। डीन और विभागाध्यक्ष का यह रोटेशन बहुत घातक सिद्ध हुआ है। निश्चय ही अकर्मण्य, अयोग्य व अक्षम लोग उच्चतम पद तक पहुँचते हैं। संभव है अयोग्य, अक्षम लोगों की यह मांग रही हो, और निश्चय ही उनके अनुकूल भी है ही, परंतु इससे गुणात्मकता का ह्रास हुआ है। कुलपति का भी टर्म रहता है और टर्म समाप्त होने पर वह व्यक्ति पूर्व पद पर काम करता है। कितना उत्पीड़न है उस व्यक्ति का, जो अपने से कनिष्ठ व्यक्ति के नीचे काम करे। योग्यता तथा क्षमता के आधार पर चयन हो और फिर उसे उसकी सेवानिवृत्ति तक काम का अवसर दिया जाय। संभव है अपवाद स्वरूप कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन न कर सकें तो सम्मानजनक विकल्प खोजा जाना चाहिये। यही हाल कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों का है। सावधिक पदोन्नतियों से एक सेकण्डरी उत्तीर्ण शिक्षक भी पोस्ट ग्रेजुएट की ग्रेड तक पहुँच सकता है। एक भीड़ की तरह आगे बढ़ते जाते हैं। कोई दक्षता अवरोध (ई.बी. एफिशियेन्सी बार) पहले ही तरह नहीं हैं। वार्षिक मूल्याँकन एक औपचारिकता रह गई है।

हाल ही में मेडिकल कॉलिजों में प्रिन्सिपल की भी टर्म निश्चित कर बाद में हटाया जाने लगा है। यह पुनः एक आत्मघाती बदम है। हॉस्पिटल सुपरिन्टेन्डेन्ड, विभागाध्यक्ष आदि पर तो यह पहले ही लागू था। कितना गलत निर्णय है यह सभी समझा जा सकता है जब मुख्यमंत्री को रोटेशन से मंत्री बना दिया जाय। क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री, मुख्यसचिव, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य सभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति का भी रोटेशन होना चाहिये? क्या इन सभी को रोटेशन के आधार पर अपने पद से नीचे के पद पर लगाया जा सकता है। यही नहीं सत्ता व राजनीति के उच्च पदों पर बैठे लोगों को अपनी पीढ़ियों तक अथवा आजन्म अपने पद पर क्यों बने रहना चाहते हैं। क्यों क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदाय, धर्म के नाम पर देश का अहित करके अथवा विभाजक रेखाऐं खींच कर भी क्यों सत्ता में रहना चाहते हैं?

मकसद केवल एक है अपने दलीय स्वार्थ की ही नहीं, निजी व जातिगत स्वार्थ की पूर्ति करना। राज्य सरकारों की रीति-नीति के कारण शिक्षा, चिकित्सा ही नहीं प्रत्येक विभाग का स्तर गिरा है। वह और भी गिरने वाला है। राजस्थान ने ऐसे कई आत्मघाती निर्णय लिये हैं। हर रोटेशन व परिवर्तन के पीछे अपने लोगों को अथवा किसी न किसी रूप में स्वार्थपूर्ति ही उद्देश्य रहता है। यह रोटेशन व 'टर्म' की कुप्रथा जितनी जल्दी समाप्त हो राजस्थान का भला होगा। यह निश्चित है कि स्तर निरंतर गिरता ही रहेगा। क्यों दर्द होता है, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद से हटने पर, क्यों नहीं स्वयं हटना चाहते लोग? राजस्थान में तो मुख्यमंत्री के रोटेशन की बात कभी से चल रही है और वे कई टर्म तक मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, फिर वे स्वतः पद क्यों नहीं छोड़ देते या फिर उप मुख्यमंत्री बनकर देखें कि कितना दर्द होता है। योग्य व्यक्ति अवश्य पदासीन रहे और अयोग्य व्यक्ति का चयन ही न हो यह हर क्षेत्र में लागू होना ही श्रेयस्कर है।

–अतिथि सम्पादक,
कैलाश विहारी वाजपेयी,
(स्वतंत्र चिंतक व लेखक)

अर्थव्यवस्था आशावाद पर आधारित नहीं होती है, इसे पक्का धरातल चाहिए

डॉ. रामावतार शर्मा

कहा जाता है कि मनोविज्ञानिक और अर्थशास्त्री के अनुमान और निष्कर्ष कभी भी बदल सकते है क्योंकि मन और अर्थव्यवस्था किसी भी क्षण दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। आज से चंद सप्ताह पहले भला किसको पता था कि अमरीकन सरकार द्वारा ब्याज वृद्धि के कारण उसके अपने सशक्त बैंक डूब जायेंगे। ध्यान रहे वहां का सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया होने के चंद दिन पहले ही वर्ष का सर्वोत्तम बैंक घोषित हुआ था। बैंक सरकार द्वारा तेजी से ब्याज दर बढ़ाने की वजह से डूबा क्योंकि उसका बहुत-सा पैसा सरकार के ही लंबी अवधि के बॉन्ड्स में लगा था जिनकी कीमतें ब्याज दर बढ़ने के फलस्वरूप घट गई थी। यह घटना बताती है कि अर्थव्यवस्था मन की तरह ही गतिशील और वाचाल होती है।

मानव स्वभाव फिर भी तकरीबन हर कार्य के बारे में कुछ अंदाजे और उम्मीदें लगाता है। नेतृत्व अच्छे दिन आने की घोषणा करता है, जनता किसी न किसी व्यक्ति से चमत्कार की उम्मीद करती है, उसमें दैवीय शक्तियों का आभास पाती है, पर धरातल पर कुछ और ही हो रहा होता है जिसे स्वीकारने से अहंकार को चोट पहुंचती है। यही कारण है जिसकी वजह से असत्य और झूठी आशा फलती-फूलती रहती है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच जीवन चलता रहता और असंख्य नागरिक सीमित लोगों की सफलता के उदाहरणों के बीच अवसाद और दरिद्रता की तरफ सरकते जाते हैं।

फरवरी 2022 में अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने बड़े आत्म विश्वास के साथ घोषणा की थी कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 में 8 - 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। वित्तमंत्री की घोषणा के 15 दिन बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांता दास ने इस वृद्धि दर को घटा कर 7.8 प्रतिशत कर दिया। दास के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4.5 प्रतिशत के अंदर ही रहेगी। उसके बाद विश्व में बहुत कुछ हुआ और अब तो स्पष्ट हो गया है कि वित्तमंत्री और रिजर्व बैंक गवर्नर दोनों ही गलत सिद्ध हुए हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने पूरे विश्व में महंगाई तो बढ़ाई ही, साथ में मुद्रा के प्रवाह को भी संकुचित कर दिया। अमेजन के बेजॉस जैसे लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अपना रोकड़ा बचा कर रखो, शायद काम आए।

अमेरिका और यूरोप में भारत का निर्यात घटने और आयात बिल बढ़ने से भारत का चालू खाता घाटा बढ़ने लगा है जो किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है।

अब जी डी पी के 6.5 या इसके भी कुछ नीचे रहने की संभावना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.5 प्रतिशत के पार चल रही है। रिजर्व बैंक ने 2023 - 24 की जी डी पी दर 6.4 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.3 का अंदाजा दिया है। परंतु कितने लोग हैं जो रिजर्व बैंक की इस बात पर भरोसा कर रहे हैं? असफल या अत्यधिक मानसून, कॉरपोरेट जगत के मुनाफे में बड़ी गिरावट, बैंक से लोन में गिरावट या फिर तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र वृद्धि जैसी कितनी ही घटनाएं आर बी आई के अंदाजों को धराशायी कर सकती हैं। कुछ विशेषज्ञ इस वर्ष की जी डी पी दर के 5.5 प्रतिशत तक गिरने की बात करने लगे हैं। इन हालातों को देखते हुए आर्थिक प्रगति के बड़े दावे आश्चर्य पैदा करते हैं। आशावादी होना अच्छी बात है पर आधारहीन आशाएं भला किस काम की?

भारतीय जी डी पी का आधा भाग सरकार और नागरिक उपभोक्ताओं से आता है और हमारी अर्थव्यवस्था स्थानीय उपभोग के दम पर ही खड़ी है। अब यदि हम बजट पर नजर डालें तो उसमें कहीं भी बचत और उपभोग की वृद्धि को प्रोत्साहन देना नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता जिससे सामान्य उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो सके। जब किसी देश का मध्यम वर्ग सिर्फ रोजी-रोटी में उलझ कर रह जाता है तो वहीं से उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है। 45 लाख करोड़ के इस वर्ष के बजट में आयकर 9 लाख करोड़ आंका गया है जिसमें कॉरपोरेट आयकर भी शामिल है। सामान्य नागरिकों का आयकर में अनुपात नगण्य सा ही है और आयकर के निचले स्लैब में तो लगातार कमी आ रही है। यह कमी इंगित कर रही है कि भारत का मध्यम वर्ग आर्थिक कठिनाई के दौर से गुजर रहा है।

कोविड काल की रुकी हुई उपभोक्ता मांग अब ठंडी पड़ जायेगी। बढ़ी हुई कीमतें बाजार में मांग को कम कर सकती हैं और ब्याज दरों के लगातार बढ़ने से ई एम आई की अवधि बढ़ जाएगी। 6.5 प्रतिशत से बढ़ कर ब्याज दर 9 प्रतिशत को पार कर रही है तो बहुत से लोग सेवा निवृत्ति के बाद तक भी अपने कर्ज की मासिक किश्त चुकाते रहेंगे जिसके कारण उनका जीवन स्तर नीचे ही रहेगा। आज जहां कम कीमत के फ्लैट्स बेचने में काफी जोर आ रहा है वहीं करोड़ों रुपए कीमत वाले बहुत ही महंगे फ्लैट्स आनन फानन बिक रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि बड़े धन का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरह हो रहा है, भारत में धन और संपदा का फैलाव नहीं बल्कि संकुचन हो रहा है जो एक चिंता का विषय है।

भारत में जिस उपभोग की बात की जा रही है उसका 80 प्रतिशत तो सरकार द्वारा ही किया जाता है। अब सरकार सब्सिडी और मनरेगा में कटौती कर रही है। इस साल के बजट में सरकार के खर्चे में मात्र 1.27 प्रतिशत की वृद्धि आंकी जा रही है। जब पैसा नहीं होगा तो उपभोग कैसे होगा? इसलिए आंतरिक उपभोग अकेले के दम पर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का चलना संभव नहीं है परंतु निर्यात को बढ़ाने में भारत अभी तक सफल नहीं हुआ है। इसके अलावा गल्फ राष्ट्रों से आने वाले डॉलर्स अब कम हो चले हैं, विदेशी पर्यटक काफी कम होते जा रहे हैं, आई टी इंडस्ट्री कमजोर पड़ती नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आना स्वाभाविक है। ये सब कारण मिल करे रुपए को कमजोर बना रहे हैं। भारत कई क्षैत्र में विश्व का सबसे बड़ा आयातक है इसलिए कमजोर रुपया करेंट अकाउंट के घाटे को और बढ़ा रहा है। यदि भारत निर्यात बढ़ाने में सफल होता है तो कमजोर रुपया फायदे की बात हो सकती है परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है।

सरकार दस लाख करोड़ की पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर खर्च करने का दावा बजट में कर रही है। क्या सरकार इतना धन जुटा पाएगी? क्या इस पूंजी का कुछ हिस्सा देश के निचले वर्ग तक पहुंच पाएगा? ध्यान रहे, सरकार के इस खर्चे में बहुत सी वस्तुओं का निर्यात करना पड़ेगा जिसके कारण विदेशी पूंजी भंडार पर बड़ा दबाव आएगा क्योंकि वैश्विक मंदी के कारण निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। इस तरह से भारत सामान के साथ-साथ मुद्रास्फीति और महंगाई का भी आयात करेगा। यह एक विकट स्थिति है जिसमें से निकलना आसान नहीं है। अब यदि अमेरिका में मंदी आती है तो उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा क्योंकि भारत में बड़ा विदेशी निवेश डॉलर के रूप में ही आता है।

एलन ग्रीनस्पैन 90 वर्ष से ऊपर की उम्र के व्यक्ति हैं। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के लंबे समय तक चेयरमैन रहे हैं और जो कहते हैं सपाट कहते हैं। उनके अनुसार ;हम अर्थव्यवस्था के बारे में कभी भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं फिर भी हम ऐसा करने का नाटक करते हैं। हम फिर भी भविष्यवाणी करते रहते हैं।;

– डॉ. रामावतार शर्मा,
(चिकित्सक एवं लेखक)

पांच हज़ार वर्ष पुरानी धरोहर के अवशेष पुलिस को सौंपे

■ **बनास नदी के समीप बसने वाली प्राचीन धरोहर के अवशेष जमा कराए**

भीलवाड़ा, (निसं)। जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश नवहाल व सुप्रसिद्ध पुरात्तवेत्ता डॉ. जीवनसिंह खरकवाल, डॉ. तमेघ पंवार ने मंगरोप पुलिस स्टेशन पर पुलिस अधिकारियों को बनास नदी के समीप बसने वाली लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन धरोहर के अवशेष व मिट्टी के बरतनों के टुकड़े जमा कराए।

जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश चन्द्र नवहाल ने बताया कि डॉ. जीवन सिंह खरकवाल, निदेशक, साहित्य संस्थान, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्या पीठ विश्वविद्यालय के नेतृत्व में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के डॉ. तमेघ पंवार व तीन शोध विद्यार्थियों के साथ मंगरोप बनास नदी के समीप लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन जनबसाव के अवशेषों का अध्यनन किया। इससे यह बात उभर कर आई कि यह लगभग 8-10 हेक्टर के क्षेत्र में यह बस्ती थी। बनास के पास होने से जल उपलब्धता सुगम थी।

यहां के निवासी मिट्टी के विशेष बरतन बनाने में निपुण थे। इनका अन्य जनबसाव की कॉलोनी से सम्पर्क रहा। यहां यह स्थान तीन बार बस कर उजाड़ हुआ। जिसकी अवधि टीम को यहां मिले साक्ष्य अनुसार लगभग 5000 वर्ष, लगभग 2000 वर्ष व लगभग 1100 - 1200 वर्ष स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

यहां मिले साक्ष्यों को स्थानीय मंगरोप थाने में पुलिस प्रशासन को स्थल की पूरी जानकारी देकर सौंपे गये। पुलिस अधिकारीयों को इसके महत्व व धरोहर के पुरातात्विक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी अवगत कराया ताकि वे इसके वे इसके संरक्षण में सहभागी हो सके। यह भीलवाड़ा जिले की ऐसी धरोहर है जिसके अध्यनन व शोध की महती आवश्यकता है। जिसके अनुसार यह साबित होता है कि यह प्राचीनतम मानव बसाव रहा है, जिसके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है।

जेईई-मेन प्रवेश परीक्षा आज से

कोटा, (निसं)। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन अप्रैल गुरुवार 6 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसके लिए विद्यार्थी भी तैयार हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी तैयारियां पूरी हो गई है।

बीई-बीटेक के लिए जेईई-मेन अप्रैल परीक्षा 6, 8, 10, 11, 12, 13 एवं 15 अप्रैल होगी। वहीं 12 अप्रैल को बीआर्क के लिए परीक्षा होगी। परीक्षाएं दो शिफ्टों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से 6 बजे के बीच में होगी। देश के 315 और विदेश में 15 शहरों में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। अप्रैल परीक्षा के लिए 9 लाख 40 हज़ार विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। राजस्थान में 17 शहरों में परीक्षा होगी, जिसमें अजमेर, अलवर, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर व उदयपुर में परीक्षा केन्द्र होंगे। पहले दिन कोटा शहर में दो परीक्षा केंद्र शिव ज्योति इंटरनेशनल ल स्कूल रानपुर एवं राजीव गाँधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन झालावाड़ रोड़ में परीक्षा होगी।

एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के एजुकेशन एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जेईई-मेन 2023 के लिए यूनिक कैंडिडेट की संख्या 12 लाख तक पहुंच गई है जो की गत वर्ष से 1 लाख ज्यादा है। पूर्व में जनवरी परीक्षा के लिए 9 लाख स्टूडेंट्स पंजीकृत हुए एवं अब अप्रैल परीक्षा के लिए 3 लाख 20 हज़ार स्टूडेंट्स ने नए आवेदन किया है ये वे हैं पहली बार अप्रैल परीक्षा में बैठ रहे है। जेईई-मेन के आधार पर मिलने वाले एनआईटी की संख्या करीब 24 हज़ार है ऐसे में एनआईटी की हर सीट के लिए करीब 50 स्टूडेंट्स ने कम्पटीशन रहेगा। पूर्व में जब परीक्षा शहर जारी किए गए तो उसमें स्टूडेंट्स को चारों विकल्पों में भरे गए परीक्षा शहर मिलने पर एनटीए को ई-मेल कर जानकारी दी गई थी।

भारतीय पुलिस की खराब स्थितिः सम्मान और संसाधनों की मांग

मरियम अबूहैदरी

एक पशु कार्यकर्ता के रूप में पशु क्रूरता के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए मैं अक्सर पुलिस स्टेशनों का दौरा करती हूं। आज, जब मैंने एक पुलिस स्टेशन का दौरा किया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक फिल्म के सेट पर थी जिसे आसानी से अलग किया जा सकता था। छत को ठीक से स्थापित करने की आवश्यकता थी, अन्यथा बारिश का पानी अंदर बह जाएगा। स्टेशन की स्थिति दयनीय थी।

भारत में पुलिस की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। उन्हें बिना किसी उचित सुविधा या समर्थन के कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। कई मामलों में, पुलिस थाने जर्जर, गंदे और पर्याप्त रूप से सुविधाजनक नहीं पाय जाते हैं। विकास के पथ पर चलने का दावा करने वाले देश भारत के लिए यह शर्मनाक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें वास्तव में अपने 20 अध्यक्ष पद पर गर्व महसूस करना चाहिए?

थानों के लगभग हर पहलू में धन की कमी स्पष्ट है। उन्हें अधिक बजट देने की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें केवल 4 आकार के प्रिंटिंग पेपर का एक पैकेट दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें इसे संयम से इस्तेमाल करना होगा, जो उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में बाधा बन सकता है। यह शर्म की बात है कि देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार इतनी महत्वपूर्ण संस्था को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं दिए गए हैं।

भारत में पुलिस की दुर्दशा अन्य देशों के पुलिस बलों के विपरीत है, जहां अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। यह समय है कि भारत सरकार पुलिस बल में निवेश के महत्व को समझे और उन्हें वे संसाधन उपलब्ध कराये जिनकी उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यकता है। एक पुलिस बल जो अच्छी तरह से वित्त पोषित और अच्छी तरह से सुसज्जित है, नागरिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और देश में अपराध दर को कम करने में सक्षम होगा।

यदि हम अन्य देशों की स्थितियों की तुलना करें तो उन राष्ट्रों में, पुलिस अच्छी तरह से सम्मानित और अच्छी तरह से सुसज्जित है, और उनके काम करने की स्थिति बहुत बेहतर है। राजस्थान में स्थिति गंभीर है। पुलिस स्टेशन जर्जर अवस्था में हैं, अधिकारी कम प्रशिक्षित हैं, और उन्हें अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए अधिक उपकरण व प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) के अनुसार, जनवरी 2021 तक, राजस्थान में कुल 85,195 पुलिस कर्मी थे, जिनमें 66,051 पुरुष और 19,144 महिलाएं शामिल थीं। यह प्रति 100,000 जनसंख्या पर 144.2 के पुलिस-जनसंख्या अनुपात पर काम करता है, जो राष्ट्रीय औसत 138.3 से अधिक है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव द्वारा 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि राजस्थान के 60 पुलिस स्टेशनों में शौचालय, पीने के पानी या पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग लॉकअप जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। अध्ययन में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में अधिक निवेश की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

हमें पुलिस के लिए बड़े बजट की मांग करने की जरूरत है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस थानों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय और स्वच्छ वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं हों। पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता दी जानी चाहिए। सरकार के लिए अधिक पुलिस अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण का सही समय है। भारत में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, और कई कुशल व्यक्ति बेरोजगार हैं। सरकार को इन व्यक्तियों को पुलिस अधिकारियों के रूप में भर्ती करके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास किसी भी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक कौशल है। ऐसा करने से, न केवल सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि पुलिस बल अच्छी तरह से कार्यरत है और देश की सेवा करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित है।

– मरियम अबूहैदरी,
पशु कार्यकर्ता

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 6 अप्रैल, 2023

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, गुरूवार, विक्रम संवत 2080, हस्त नक्षत्र दिन 12:41 तक, व्याघात योग रात्रि 2:30 तक, बव करण दिन 10:04 तक, चन्द्रमा रात्रि 1:10 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मिथुन, बुध-मेष, गुरू-मीन, शुक्र-मेष, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज वैशाख स्नान आरम्भ होगा। आज हनुमान जन्मोत्सव, पूर्णिमा व्रत, सत्यव्रत, चैत्री पूर्णिमा, हनुमान जयन्ती (द. भारत में), सर्वदेव दमनोत्सव और जैन आयंबिल ओली समाप्त होगी। शुक्र वृष में प्रवेश 10:59 पर करेगा। आज मेला सालासर बालाजी और सत्यपुरी धाम वाटिका है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: सूर्योदय से 7:50 तक, चर 10:57 से 12:30 तक, लाभ-अमृत 12:30 से 3:36 तक, शुभ 5:09 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 6:42

मेष

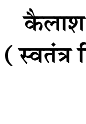

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

वृष

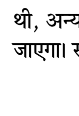

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

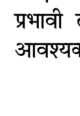

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में उचित सफलता मिलेगी।

कर्क

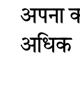

व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

सिंह

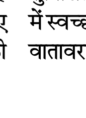

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

तुला

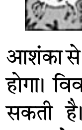

व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में आपसी वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक

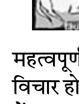

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

धनु

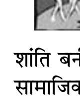

व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर

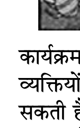

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

कुंभ

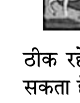

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

मीन

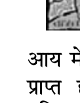

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।